संपादकीय

सत्यांश

आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी

पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की 67 सीटों के साथ एकतरफा जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर के लिए यह पहला अवरोधक झटका है। इस चुनाव में जहाँ कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया और उसे एक भी सीट पर विजय हासिल न हो सकी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी विपक्षी पार्टी बनने लायक विधानसभा की दस प्रतिशत यानी सात सीटें भी नहीं मिल सकीं। भाजपा को केवल तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा। सन् 1993 में जब पहली वार दिल्ली विधानसभा बनी तो भाजपा को 49 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, किंतु बाद के 1998, 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में उसे बहुमत तो नहीं मिला, पर हमेशा मजबूत विरोधी दल लायक सम्मानजनक सीटें मिलती रहीं। ये न्यूनतम 14 और अधिकतम 32 तक रही हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत के साथ केन्द्र में सत्तासीन होने का मौका मिला है। इसके बाद से सभी विधानसभा चुनावों में उसे बढ़त मिली है, ऐसे में केन्द्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय चौंकाने वाली है। यह ठीक है कि भाजपा की हार से यह आम आदमी पार्टी की जीत अधिक है। सन् 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनी। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद जल्दी दुबारा चुनाव ही बेहतर विकल्प था, लेकिन इसे टाला गया। पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार की तरह मोदी सरकार भी चुनाव को टालते हुए किसी प्रकार पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की रणनीति में उलझी रही, जो बिल्कुल अव्यावहारिक, अदूरदर्शी और औचित्यहीन प्रयास था। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने को चुस्त-दुरस्त किया और जनसामान्य में यह संदेश फैल गया कि चुनाव से अधिक येन-केन-प्रकारेण सरकार बनाने में भाजपा की रुचि अधिक है।

सन् 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव-परिणाम से कांग्रेस की खस्ता हुई हालत का फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला। कांग्रेस का वोट पूरी तरह खिसक कर आम आदमी पार्टी की ओर चला गया, जिससे दिल्ली में न केवल उसकी जीत सुनिश्चित हुई, बल्कि बड़ी भी हुई। भाजपा का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसा ही है। केन्द्र में मजबूती से चल रही मोदी सरकार के तेज कामकाज के बावजूद दिल्ली मे भाजपा का जनाधार तात्कालिक रूप से भी क्यों नहीं बढ़ पाया, यह जिज्ञासापरक है। चुनावी हार-जीत से परे दिल्ली हमेशा से भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन जिस तरह आनन-फानन में एक अराजनीतिक व्यक्ति को पार्टी व सरकार का नेतृत्व करने का जिम्मा दिया गया, उससे दिल्ली भाजपा में नेतृत्व की दरिद्रता उजागर हुई। केन्द्रीय नेतृत्व का यह अहंकार भी प्रकट हुआ कि किसी भी उल्टे-सीधे फैसले को मानने के सिवा कार्यकर्ताओं-समर्थकों के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि सारे देश में नए नेतृत्व की राजनीति-रणनीति के कारण डुग्डुगी बज रही है, विजय-पताका फहरा रही है।

किरण बेदी एक ईमानदार, पर सख्त प्रशासक रही हैं, परंतु प्रशासन चलाना चुनाव के बाद बनी सरकार का काम है। आजकल के चुनाव जीतने-जितवाने में अच्छे प्रशासक की छवि कारगर ही हो - यह आवश्यक नहीं, बल्कि दलीय राजनीति वाले लचीले लोकतंत्र में इसका विपरीत प्रभाव भी होता है। किरण बेदी का चुनाव लड़ना जितना अच्छा था, उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार पहले घोषित करना उतना ही अनावश्यक। भाजपा ने एकाएक यह जोखिम उठाया, जिसका थोड़ा खामियाजा उसे उठाना पड़ा है। वहीं यदि किरण बेदी आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार होतीं, तब क्या होता? अस्तु, तमाम प्रचार-प्रसार के बावजूद भाजपा के वोट बैंक में बढ़ोतरी न होना चुनावी पराजय का मुख्य कारण है।

आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, जिसे मौजूदा राजनीतिक परिवेश, परिपाटियों-परंपराओं, नियमों-कानूनों के भीतर रहते हुए सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव रखनी होगी। एक बेहतर, संवेदनशील और कार्योत्सुक सरकारी कामकाज का नमूना पेश करना होगा। दिल्ली अव्यवस्थाओं के साथ अपेक्षाकृत व्यवस्थित शहर है, कई प्रशासनिक इकाइयों से संचालित होने वाली राजधानी है, जिसे भारत के अन्य राज्यों की तरह पूर्णराज्य नहीं बनाया जा सकता। इन सबको समेटे दिल्ली में बेहतरीन लोकतांत्रिक शासन-प्रबंध होने की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें साकार करने का दायित्व अब आम आदमी पार्टी पर है।